डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जून, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 जून, 2024

| वर्ष 68 | अंक 02 | भोपाल | 16 जून, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में अनुभवी और युवा चेहरे शामिल

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों की सेवा और देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। यह नया मंत्रिमंडल कई मायनों में खास है, जिसमें अनुभव और युवा उत्साह का अद्वितीय संयोजन देखने को मिलता है।

शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने और मंत्रिमंडल के साथ मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। आज शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई। यह मंत्रिमंडल युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है, और हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सभी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभारी हूं जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। भारत हमेशा अपने मूल्यवान साझेदारों के साथ मानव प्रगति की दिशा में काम करेगा।"

इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ कई प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, और निर्मला सीतारमण जैसे अनुभवी नेताओं को प्रमुख पदों पर बनाए रखा है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हैं। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में अन्य कैबिनेट मंत्रियों में जगत प्रकाश नड्डा, नए मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव जैसे अनुभवी नेताओं के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरदीप सिंह पुरी जैसे ऊर्जावान नेताओं को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी और बिहार के नेता जीतन राम मांझी प्रमुख हैं।

इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह, डॉ. जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जाधव प्रतापराव गणपतारावं और जयंत चौधरी प्रमुख थे।

गरीब और जरूरतमंदों को मिले दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ : श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल ने की पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ ग़रीब और ज़रूरतमंदों को मिले। हितग्राहियों के चिन्हांकन में उनकी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। पशुपालकों को पशु प्रदान करते समय अच्छी नस्ल के स्वस्थ पशु प्रदान करे। उन्हें पशुओं के रख-रखाव आदि की जानकारी दे। श्री पटेल ने उक्त निर्देश राजभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि दुधारु पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत पशुपालकों के लिए दुग्ध संग्रहण की विशेष व्यवस्था बनाए। श्री पटेल ने दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य तथा उपलब्धि, बजट एवं आगामी प्रस्तावों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना के लक्ष्य को आवश्यकतानुसार बढ़ाएं और उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। राज्यपाल श्री पटेल ने बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति क्षेत्रों में पशुप्रदाय योजना की विगत और वर्तमान स्थिति की तुलनात्मक समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से पशु प्रदाय के लिए पात्रता निर्धारण, पशु चयन और वितरण की समस्त प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली।

राजभवन के जवाहर खण्ड में आयोजित बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खाण्डेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चन्द गुप्ता, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाकांत भार्गव, राज्यपाल के विधि अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव, संचालक पशु पालन एवं डेयरी विकास और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सेवा, सुशासन से ग़रीब कल्याण

भोपाल : मध्यप्रदेश ने पिछले छह माहों के सुशासन के प्रयासों से यह जाहिर कर दिया है कि गरीबी पर ठोस प्रहार कर गरीब परिवारों को गरीबी के कुचक्र से बाहर लाया जायेगा। इसके लिए जरूरी है कि उन परिवारों को नागरिक सेवाओं के पहुंच के दायरे में लाया जाये। उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाई जाये। उनके लिए सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की श्रंखला चलाई जाये।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिये सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास तथा सबका प्रयास का नारा वंचितों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों की आधारशिला बन गया है। ज़रूरतमंदों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता दी जा रही है।

गरीब कल्याण: संकल्प से सिद्धी की ओर

गरीब हितैषी पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को देशभर में पहचान मिली है। उन्होंने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। तीन दशक से हुकुमचंद मिल के मजदूर न्याय की गुहार लगा रहे थे, उनकी इस गुहार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने न केवल सुना बल्कि उन्हें एक बड़ी राहत प्रदान की।

श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने अथक प्रयासों का सिलसिला सतत रूप से जारी रखा। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना 2.0 में 30 हजार 500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि दी गई। मजदूरों की दिव्यांगता के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। इसी के साथ ही श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

राज्य शासन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, डबल इंजन सरकार का यह संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। शासन की जन हितैषी योजनाएं- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचने लगी। गरीबों को न केवल न्याय मिले बल्कि उन तक न्याय पहुंच सके इसका प्रबंध सरकार ने किया है।

कमजोर वर्ग का विकास पहली प्राथमिकता

तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए प्रति बोरा से बढ़कर 4 हजार रुपए किया गया है। लगभग 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड रुपए से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य हो रहे हैं जिससे 11 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पांच माह में 5000 से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। शिवपुरी जिले में सर्वाधिक लगभग 1103 आवास पूर्ण किए गए हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों जिनमें योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की अधिक संख्या थी उन ग्रामों में कॉलोनी बनाकर आवास बनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन मन मिशन के तहत प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के अविद्युतीकृत घरों तक बिजली पहुंचाने की कार्य योजना स्वीकृत कर ली गई है।प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7300 से अधिक जनजातीय बहुल ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और कौशल विकास के कार्य हो रहे हैं। आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के खातों में जनवरी से लेकर अभी तक 148 करोड रुपए से अधिक की राशि आंतरित की जा चुकी है।

प्रदेश सर्व स्पर्शी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समाज के सभी वर्गों की विकास में समान भागीदारी के लिए गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में पहली बैठक की

महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा PACS को बहु-सेवा समितियों में बदलने पर जोर

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसकी पायलट परियोजना को लागू किया है

नई दिल्ली, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) ने नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव, एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) और अन्य हितधारकों के साथ पहली बैठक की।

समिति ने 11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM-FME) आदि के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण की योजना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर (custom hiring centre), प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसमें देश भर में इस योजना को लागू करने के लिए स्थानीय स्तरों पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा।

पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), नाबार्ड परामर्श सेवाएं (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय में लागू किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों, एनसीसीएफ, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) आदि के सहयोग से 500 अतिरिक्त PACS में पायलट परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों, जैसे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) ने परियोजना के तहत भंडारण क्षमता और अन्य कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त PACS की पहचान की है।

समिति के सदस्यों ने इस बात पर भी चर्चा की कि योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ गोदामों को जोड़ने के संभावित विकल्प भी शामिल हैं।

कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प दोहराया

नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया पहला निर्णय किसानों के हित में था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मंत्री ने यह भी जोड़ा कि एनडीए सरकार पिछले दस वर्षों से किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रही है और उनका मंत्रालय इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता रहेगा।

कार्यभार संभालने के बाद, मंत्री ने मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों, जिनमें स्वच्छता कार्यकर्ता भी शामिल हैं, के साथ बातचीत की। उन्होंने उन्हें टीम के रूप में काम करने और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मंत्रालय में कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का भी दौरा किया और देश में कृषि परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए फसलों के उत्पादन और सूखे की तैयारी की सुविधाओं का अवलोकन किया।

बाद में, उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की और मंत्रालय के कार्य में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों और ग्रामीण विकास के कल्याण के लिए सरकार के घोषणापत्र को सौंपते हुए सभी से इसके पूर्णता की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं और अधिकारियों से घोषणापत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता का जीवन सुधारना मंत्रालय का मिशन होना चाहिए।

राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी ने भी कार्यभार संभाला

श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी ने भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। माननीय मंत्रियों का स्वागत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा, डेर के सचिव श्री हिमांशु पाठक और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि में वृद्धि

विदिशा : विदिशा जिले में रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य (2275 प्लस बोनस 125 कुल 2400 रूपये प्रति क्विंटल) पर गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है।

म.प्र.शासन द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन की अवधि बढ़ाई गई है। कृषि उपज मंडियों में गेंहू की आवक एवं किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रदान करने हेतु पुनः उपार्जन की अवधि में वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार जिले में अब गेंहू का उपार्जन 25 जून 2024 तक किया जाएगा। विस्तारित अवधि में विकासखंड बासौदा, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज, विदिशा, ग्यारसपुर इस प्रकार कुल 9 उपार्जन केन्द्रों पर उनके सम्मुख दर्शित स्थल पर गेंहू उपार्जन का कार्य किया जाएगा।

केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है

बासौदा विकासखंड की कृषि उपज मंडी गंजबासौदा स्थित उपार्जन केंद्र विपणन सहकारी समिति मर्यादित बासौदा, कुरवाई की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुरवाई, लटेरी की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित लटेरी तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोदाम ग्राम भीलखेड़ी स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित लटेरी, शमशाबाद नटेरन की कृषि उपज मंडी शमशाबाद स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित नटेरन शमशाबाद, सिरोंज की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित सिरोंज, विदिशा की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित विदिशा तथा स्टील सायलो पठारी हवेली स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित विदिशा के अलावा ग्यारसपुर विकासखंड की कृषि उपज मंडी गुलाबगंज स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित बर्रीघाट गुलाबगंज इन सभी 09 उपार्जन केन्द्रों पर 25 जून तक पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी कार्य किया जाएगा।

अतः गेहूं उपार्जन से समस्त वांछित कृषकों से अपील की गई है की शासन द्वारा बढ़ाई गई विस्तारित अवधि 25 जून में उक्त उपार्जन केन्द्रों से गेहूं उपज की तौल कराकर समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्राप्त करें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन की एंट्री

दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को दो AI एंकर AI कृष और AI भूमि लान्च करेगा

ये एंकर देश-विदेश की पचास भाषाओं में बात कर सकते हैं

नई दिल्ली, दूरदर्शन एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है क्योंकि 9 साल की अपार सफलता के बाद डीडी किसान 26 मई 2024 को एक नए रंग रूप और एक नए अंदाज के साथ, भारत के किसानों के बीच आ रहा है। जहां चैनल की प्रस्तुति एक नए अंदाज में होने जा रही है।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के इस युग में ये देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बनने जा रहा है जहां AI एंकर पर सभी की निगाहें रहेंगी। दूरदर्शन किसान दो AI एंकर AI कृष और AI भूमि लान्च करने जा रहा है। ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर हैं, जो हूबहू इंसान की तरह ही हैं और इंसानों की तरह ही काम कर सकते/सकती हैं। ये एंकर बिना रुके या फिर बिना थके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज़ पढ़ सकते हैं।

किसान दर्शक इन्हें कश्मीर से तमिलनाडु और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के सभी राज्यों में देख

पाएंगे। ये AI एंकर देश विदेश में हो रहे कृषि अनुसंधान, अनाज मंडियों में हो रही उठापटक या फिर मौसम की फेरबदल, हर आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। इन एंकर की एक खास बात यह भी है कि ये देश-विदेश की पचास भाषाओं में बात कर सकते हैं।

डीडी किसान के उद्देश्यों में शामिल कुछ खास तथ्य

डीडी किसान देश का एक मात्र टीवी चैनल है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किसानों को समर्पित की गई है। इस चैनल की स्थापना 26 मई 2015 को की गई थी।

डीडी किसान चैनल की स्थापना का उद्देश्य था कि वह हमेशा सजग रहते हुए मौसम, वैश्विक बाजारों इत्यादि में होने वाले बदलावों से किसानों को अवगत कराता रहे, ताकि किसान पहले से ही उपयुक्त योजनाएं बना सकें और समय पर सही निर्णय ले सकें। डीडी किसान चैनल 9 साल से इन मापदंडों पर खरा उतर रहा है।

डीडी किसान चैनल प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सभी लोगों के सामने लाने का काम भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें शिक्षित कर समग्र विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है।

डीडी किसान चैनल कृषि की त्रिआयामी अवधारणा जिसमें संतुलित खेती, पशुपालन और वृक्षारोपण शामिल हैं, को मजबूत कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के बढ़ते कदम

भोपाल : देश के 10% क्षेत्रफल वाले राज्य मध्यप्रदेश में देश की लगभग 7% आबादी निवास करती है। यहां 11 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। राज्य की कृषि उपज में विविधता मुख्यतः नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार सरल नीतियों के माध्यम से 'ईज ऑफ डूइंगबिज़नेस' सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेशनवाचार और प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। 'भारत की फूडबास्केट' कहलाने वाला मध्यप्रदेश पारंपरिक प्रथाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़कर देश के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत की फूडबास्केट कृषि क्षेत्र

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और कृषि का राज्य के जीएसडीपी में 47प्रतिशत का योगदान है, जो सरकार द्वारा की गई पहल का प्रमाण है। आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (एआई) सहित स्मार्ट खेती तकनीकों को अपनाकर राज्यडिजिटल खेती क्रांति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में, सरकार सक्रिय रूप से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का डिजिटलीकरण और कृषि आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण कर रही है।

सरकारी पहल के साथ डिजिटल खेती पर केंद्रित स्टार्ट-अपके आने से विकास के लिए महत्वपूर्ण ईकोसिस्टमका निर्माण हो रहा है। बेहतर बीज गुणवत्ता, उर्वरक निर्माण, कृषि मशीनरी और सिंचाई परियोजनाओं पर रणनीतिकफोकस के साथ, मध्यप्रदेश खेती के क्षेत्र में प्रचुर निवेश के अवसर प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश 'कृषि कर्मण पुरस्कार' का 7 बार विजेता है - यह पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य को दिया जाता है। मध्यप्रदेश भारत में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में जैविक उपज और बागवानी उत्पादन के लिए खेती का उच्च क्षेत्र है। राज्य फल, लहसुन, टमाटर, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च और प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और नींबू, गोभी और फूल और दूध सहित खट्टे फलों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्यप्रदेश शरबतीगेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जिसे भारत में गेहूं की उच्चतम गुणवत्ता माना जाता है। केवल6 वर्षों में राज्य की बागवानी उत्पादन रैंकछठवें स्थान से प्रथम पर पहुंच गयी है।

खाद्य प्रसंस्करण

वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार, जिसका मूल्य 2021 में $134.21बिलियन है, के 2030 तक 11.82%सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से भारत, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया महत्वपूर्ण वैश्विक विकास को बढ़ावा देंगे। अपने समृद्ध कृषि संसाधनों और रणनीतिक स्थान के साथ, भारत ने अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से वृद्धि देखी है, जिसने 2022 में 866बिलियन डॉलर के बाजार आकार में योगदान दिया है, जो देश के आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, मध्यप्रदेश अपने समृद्ध कृषि संसाधन और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग करके एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। राज्य का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 8.3% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उद्योग-अनुकूल नीतियों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता ने मोंडेलेज, आईटीसी और यूनिलीवर जैसे दिग्गजों से बड़े निवेश को आकर्षित किया है।

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण पहल की औपचारिकता के तहत, राज्य विभिन्न उत्पादक संगठनों को क्षमता निर्माण और समर्थन देकर असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणउद्यमों को सशक्त बना रहा है। सरकार द्वारा वित्त पोषित फूड पार्क, निजी मेगाफूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करणईकोसिस्टमको बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती है।

इस क्षेत्र में कौशल विकास पर मध्यप्रदेश का ध्यान फूडइनोवेशनहब विकसित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से उजागर होता है। राज्य में पाँच प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल को शिक्षित करने और बढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

डेयरी प्रसंस्करण

डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। अधिकांश डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं, जिसके कारण उद्योग में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरीप्रसंस्करण की जबरदस्त संभावनाएं हैं। वर्तमान में, राज्य के कुल डेयरी उत्पादन में दूध की हिस्सेदारी 48% है। सबसे तेजी से बढ़ते कुछ सेग्मेंटमें दही, पनीर, यूएचटी दूध, फ्लेवर्डदूध और छाछ शामिल हैं।

वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन में 8.6% का योगदान देता है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन की उत्पादकता वृद्धि जैसी पहल, डेयरीप्रसंस्करण क्षेत्र में सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन-शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ ने अकेले 2022-23 में 8.35 लाख केजीपीडी की औसत दूध खरीद और 7.16 लाख एलपीडी की औसत क्षेत्रीय दूध बिक्री और 1982 करोड़ रुपये से अधिक का बिक्री राजस्व दर्ज किया। 2020-2021 में राज्य में कुल दूध उत्पादन लगभग 20.01 मिलियन टन था। डेयरीप्रसंस्करण में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों में अमूल (जीसीएमएमएफ), एमपीसीडीएफ (सांची), अनिकइंडस्ट्रीज (सौरभ), पवनश्रीफूड इंटरनेशनल, स्टर्लिंगएग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नोवा) शामिल हैं।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पाद जिनकी खेती आमतौर पर राज्य भर में की जाती है, जिनमें कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/नींबू, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन शामिल हैं। अदरक, धनिया, सरसों उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आंवला और हल्दी। छिंदवाड़ा, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, बैतूल और सीहोर जैसे जिले संतरे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं जो संतरे के प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श हैं। इसी तरह, मध्यप्रदेश के बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले जो आम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां कई आम आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं जो स्थापित होने के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य सरकार ने इन जिलों की क्षमता को महसूस किया है और पहले से ही ऐसे संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो व्यावसायिक उपयोग के लिए जूस, जैम, स्क्वाश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, सुगन्धिततेल, गूदा, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम पना और स्टार्चजैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।

अनुकूल नीतिगत माहौल द्वारा सरकार से मजबूत समर्थन

राज्य सरकार ने उद्योग समर्थक नीतियां बनाकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। वित्तीय क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से 1.5 गुना है।

राज्य सरकार राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आगामी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य की प्रगति को उजागर करेगी। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न अवसरों और भविष्य में कृषि आय में वास्तविक वृद्धि लाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दृष्टिकोण से निर्देशित, मध्यप्रदेशडेयरी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करणनवाचार में सबसे आगे है। राज्य का व्यापक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान का मिश्रण, कृषि, खाद्य और डेयरीप्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में निवेशकों और हितधारकों के लिए एक आशाजनक भविष्य बनाता है।

अभी तक 48 लाख 39 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूँ खरीदी

किसानों को हुआ 11 हजार 427 करोड़ रूपये का भुगतान

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों में बनाये गये विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में अभी तक 48 लाख 39 हजार 202 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो चुकी है।

गेहूँ की खरीदी 6 लाख 16 हजार 254 किसानों से की गयी है। किसानों को 11 हजार 427 करोड़ 57 लाख रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। वर्तमान में कृषि उपज मंडी स्तर पर स्थापित 311 गेहूँ उपार्जन केन्द्रों में गेहूँ की खरीदी जारी है। इन केन्द्रों में गेहूँ की खरीदी 25 जून 2024 तक की जायेगी।

विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के केंद्र तय

अब गेहूं का उपार्जन 25 जून तक

विदिशा: विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन के केंद्र तय अब गेहूं का उपार्जन 25 जून तक – विदिशा जिले में रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य (2275 प्लस बोनस 125 कुल 2400 रूपये प्रति क्विंटल) पर गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। म.प्र.शासन द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन की अवधि बढ़ाई गई है। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक एवं किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रदान करने हेतु उपार्जन की अवधि में पुनः वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार जिले में अब गेहूं का उपार्जन 25 जून 2024 तक किया जाएगा।

केन्द्रों का विवरण – विस्तारित अवधि में विकासखंड बासौदा, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज, विदिशा, ग्यारसपुर इस प्रकार कुल 9 उपार्जन केन्द्रों पर उनके सम्मुख दर्शित स्थल पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा। केन्द्रों का विवरण इस प्रकार है – बासौदा विकासखंड की कृषि उपज मंडी गंजबासौदा स्थित उपार्जन केंद्र विपणन सहकारी समिति मर्यादित बासौदा, कुरवाई की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुरवाई, लटेरी की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित लटेरी तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोदाम ग्राम भीलखेड़ी स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित लटेरी, शमशाबाद नटेरन की कृषि उपज मंडी शमशाबाद स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित नटेरन शमशाबाद, सिरोंज की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित सिरोंज, विदिशा की कृषि उपज मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति मर्यादित विदिशा तथा स्टील सायलो पठारी हवेली स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित विदिशा के अलावा ग्यारसपुर विकासखंड की कृषि उपज मंडी गुलाबगंज स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरौंघाट गुलाबगंज इन सभी 09 उपार्जन केन्द्रों पर 25 जून तक पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी कार्य किया जाएगा। अतः गेहूं उपार्जन से वंचित सभी कृषकों से अपील है कि शासन द्वारा बढ़ाई गई विस्तारित अवधि 25 जून में उक्त उपार्जन केन्द्रों से गेहूं उपज की तौल कराकर समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषक एवं समूह पुरस्कार के लिए

राजगढ़ : सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजनांतर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के पुरस्कार के लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परियोजना संचालक आत्मा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार किसान अपने आवेदन विकासखंड स्तर पर संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय स्तर पर आत्मा परियोजना के बी.टी.एम. एवं ए.टी.एम. को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार की राशि 25 हजार रूपये, विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के रूप में 10 हजार रूपये एवं जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार के रूप में 20 हजार रूपये की राशि दी जाएगी।

मध्यप्रदेश को मिले प्रतिनिधित्व से तेजी से प्रगति पथ पर बढ़ेगा मध्यप्रदेश : डॉ. यादव

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए श्री चौहान, श्री सिंधिया, डॉ. वीरेंद्र कुमार, श्री मुरूगन, श्रीमती ठाकुर और श्री उईके को भी दी बधाई

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज शपथ ग्रहण के पश्चात तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चयन पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉ. वीरेंद्र कुमार और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बधाई एवं मंगल कामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य श्री एल मुरूगन के

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उन्हें भी बधाई दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए गए श्री दुर्गा दास उईके और श्रीमती सावित्री ठाकुर को भी मंगल कामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्राप्त प्रतिनिधित्व मध्यप्रदेश के विकास को नए आयाम प्रदान करेगा। मध्यप्रदेश तेजी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र तेजी से विकास के विविध आयाम प्राप्त करते हुए ऐतिहासिक प्रगति हासिल करेगा।

कृषि के क्षेत्र में बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिये मौसम एप की शुरुआत एक नई क्रांति

छिन्दवाडा : उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मौसम एप Mausam App IMD किसानों को सटीक और समय पर मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। इस मौसम एप का मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाना और उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एप स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवाओं की गति की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा यह एप किसानों की फसल के प्रकार, बोआई के समय और कीट नियंत्रण के उपायों के बारे में भी मार्गदर्शन करेगा।

उन्होंने बताया कि मौसम एप मौसम के विस्तृत पूर्वानुमान को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर प्रदान करता है। जिससे किसान फसल के महत्वपूर्ण चरणों में सही निर्णय ले सके। विभिन्न फसलों के लिए मौसम के अनुसार उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं, जिससे उत्पादन में सुधार होता है और नुकसान कम होता है।

एप संभावित मौसम जोखिमों जैसे तूफान, भारी बारिश या सूखे के बारे में अलर्ट भेजता है, जिससे किसान समय पर तैयार हो सकें। सहायक संसाधन के रूप में किसानों के लिए वीडियोज, लेख और विशेषज्ञों की सलाह भी उपलब्ध है, जिससे वे नवीनतम कृषि तकनीकों और उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यह एप किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इससे किसानों की उत्पादकता में वृध्दि होगी और उनके मुनाफे में भी सुधार होगा। सरकार और कृषि विभाग इस एप के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। एंड्राइड और आइओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध है। किसान इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप किसानों की उन्नति और समृध्दि के लिए प्रतिबध्द है। यह मौसम एप कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत है।

किसानों को रेज्ड बेड पर मक्का लगाने की सलाह

सिवनी : उपसंचालक कृषि श्री मोरिश नाथ ने बताया कि कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी द्वारा मैदानी अमलें को रेज्डल बेड पर मक्का लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। गतवर्ष अधिक वर्षा होने के कारण किसानों को मक्के की फसल में फसल क्षति का सामना करना पड़ा था। किसानों की मक्के फसल में अधिक वर्षा के कारण क्षति को कम करने हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को रेज्ड बेड पर मक्का लगाने की सलाह दी गई। इस वर्ष खरीफ सीजन शुरू होने के पहले ही रेज्ज बेड पर मक्का लगाने की रेजर एवं रेजर कम प्लान्टर की मांग बढ़ी है। जिले में रेजर एवं रेजर कम प्लान्टर की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ, सहायक संचालक श्री पवन कौरव, श्री प्रफुल्ल घोडेसवार एवं सहायक कृषि यंत्री श्री जे.एस.धुर्वे द्वारा कृषि यंत्र विक्रेताओं से मांग एवं आपूर्ति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिले के कृषि यंत्र डीलर विशाल ट्रेडर्स लूघरवाड़ा सिवनी द्वारा बताया गया कि लगभग 1000 रेजर किसानों को विक्रय किया जा चुके है एवं कृषकों की मांग निरन्तर बनी हुई है। इसी प्रकार सुनील कृषि यंत्र सिवनी द्वारा बताया गया कि लगभग 150 रेजर विक्रय किये जा चुके है एवं कृषक लगातार यंत्र की मांग कर रहे है। जिले में लगभग 1500 रेजर एवं रेजर कम प्लान्टर की बिक्री हो चुकी है एवं किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल सिवनी एवं मोरिस नाथ उपसंचालक कृषि यह अपील करते है मक्के की फसल को रेज्ज बेड पर लगाये एवं यंत्र की उपलब्धता अनुसार यंत्र को क्रय करें या अन्य कृषकों से किराये पर लेकर मक्के को रेज्ज बेड पर लगाये, ताकि मक्का फसल सुरक्षित रहे एवं किसानों को मक्का का अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकें।

मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के मध्य विभागों का आवंटन कर दिया है। सूची इस प्रकार है-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी	कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

1.	श्री राजनाथ सिंह	रक्षा
2.	श्री अमित शाह	गृह और सहकारिता
3.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग
4.	श्री जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक
5.	श्री शिवराज सिंह चौहान	कृषि और ग्रामीण विकास
6.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त और कॉर्पोरेट कार्य
7.	डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश
8.	श्री मनोहर लाल	आवास, शहरी कार्य और ऊर्जा
9.	श्री एच. डी. कुमारस्वामी	भारी उद्योग और इस्पात
10.	श्री पीयूष गोयल	वाणिज्य और उद्योग
11.	श्री धर्मेंद्र प्रधान	शिक्षा
12.	श्री जीतन राम मांझी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
13.	श्री राजीव रंजन सिंह	पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
14.	श्री सर्बानंद सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
15.	डॉ. वीरेंद्र कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
16.	श्री किंजरापु राममोहन नायडू	नागर विमानन
17.	श्री प्रल्हाद जोशी	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
18.	श्री जुएल ओराम	जनजातीय कार्य
19.	श्री गिरिराज सिंह	वस्त्र
20.	श्री अश्विनी वैष्णव	रेल ,सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
21.	श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया	संचार ; तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
22.	श्री भूपेंद्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
23.	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत	संस्कृति और पर्यटन
24.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	महिला एवं बाल विकास
25.	श्री किरेन रिजिजू	संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य
26.	श्री हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
27.	डॉ. मनसुख मांडविया	श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल
28.	श्री जी. किशन रेड्डी	कोयला और खान
29.	श्री चिराग पासवान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
30.	श्री सी. आर. पाटिल	जल शक्ति

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1.	श्री राव इंद्रजीत सिंह	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन,योजना और संस्कृति
2.	डॉ. जितेंद्र सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य
4.	श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव	आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5.	श्री जयंत चौधरी	कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा

राज्यमंत्री

1.	श्रीजितिन प्रसाद	वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
3.	श्री पंकजचौधरी	वित्त
4.	श्री कृष्ण पाल	सहकारिता
5.	श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
6.	श्री रामनाथ ठाकुर	कृषि
7.	श्री नित्यानन्द राय	गृह
8.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक
9.	श्री वी. सोमन्ना	जल शक्ति और रेल
10.	डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी	ग्रामीणविकास और संचार
11.	प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल	मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी, पंचायती
12.	सुश्री शोभा करंदलाजे	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम एवं रोजगार
13.	श्री कीर्तिवर्धन सिंह	पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और विदेश
14.	श्री बी.एल. वर्मा	उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
15.	श्री शान्तनु ठाकुर	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
16.	श्री सुरेश गोपी	पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन
17.	डॉ. एल.मुरुगन	सूचना एवंप्रसारण और संसदीय कार्य
18.	श्री अजय टम्टा	सड़क परिवहन और राजमार्ग
19.	श्री बंदी संजय कुमार	गृह
20.	श्री कमलेश पासवान	ग्रामीण विकास
21.	श्री भागीरथ चौधरी	कृषि
22.	श्री सतीशचंद्र दुबे	कोयला और खान
23.	श्री संजयसेठ	रक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री
24.	श्री रवनीत सिंह	खाद्यप्रसंस्करण उद्योग और रेल
25.	श्री दुर्गादास उइके	जनजातीय कार्य
26.	श्रीमती खडसे रक्षा निखिल	युवा कार्यक्रम एवं खेल
27.	श्री सुकांता मजूमदार	शिक्षाऔर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास
28.	श्रीमती सावित्री ठाकुर	महिला एवं बाल विकास
29.	श्री तोखन साहू	आवास एवं शहरी
30.	श्री राजभूषण चौधरी	जल शक्ति
31.	श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा	भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात
32.	श्री हर्षमल्होत्रा	कॉर्पोरेट कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग
33.	श्रीमती निमुबेन बांभणिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
34.	श्रीमुरलीधर मोहोल	सहकारिता और नागर विमानन
35.	श्री जॉर्ज कुरियन	अल्पसंख्यक कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालनऔर डेयरी
36.	श्री पबित्रा मार्गेरिटा	विदेश और वस्त्र

खेतों को उपजाऊ बनाने नदी, तालाब की गाद एवं मिट्टी किसानों को wबिना रॉयल्टी की नि:शुल्क मिलेगी

खरगोन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि खेतों को उपजाऊ बनाने नदी, तालाब एवं कुएं की गाद एवं मिट्टी किसानों को बिना रॉयल्टी की निःशुल्क मिलेगी। सम्पूर्ण प्रदेश में नदी, तालाब एवं कुए से निकलने वाली गाद एवं मिट्टी को किसान अपने खेतों को उपजाऊ बनाने तथा समतल करने के लिए इसका परिवहन बिना रॉयल्टी के निःशुल्क कर सकेंगे। नदी, तालाब व कुंए से निकाली गई गाद एवं मिट्टी का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

जिला खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि मप्र गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार नदी, तालाब, कुंए से निकाली गई गाद या मिट्टी की यदि किसानों को गैर व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है तो उनके आवेदन पर संबंधित शासकीय विभाग द्वारा गाद या मिट्टी को परिवहन करने की अनुमति दी जाएगी। इसके परिवहन के लिए किसानों को ना तो कोई रॉयल्टी देना होगा और ना ही परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता होगी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में नदियों, तालाबों एवं कुंओं की सफाई के दौरान निकलने वाली गाद या मिट्टी का उपयोग खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए किसान परिवहन कर सकते हैं। इसका उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

जिले में उर्वरक की उपलब्धता

बड़वानी / जिले के किसान भाईयों द्वारा खरीफ फसलों की बोनी की जा रही है। किसानों उनकी आवश्यकतानुसार रासायनिक खाद उपलब्ध कराने हेतु जिले के सहकारी क्षेत्र एवं निजी विक्रेताओं के यहा उर्वरकों का भण्डारण करवाया जा रहा है । वर्तमान में विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों एवं सहकारी समितियों में यूरिया 14009 मेट्रिक टन, डीएपी 5090 मेट्रिक टन, एनपीके 3487 मेट्रिक टन, पोटाश 2216 मेट्रिक टन, सुपर फॉस्फेट 8803 मेट्रिक टन, अमोनियम सल्फेट 37 मेट्रिक टन व निजी डीलरों की दुकानों पर यूरिया 11161 मेट्रिक टन, डीएपी 573 मेट्रिक टन, एनपीके 2109 मेट्रिक टन, पोटाश 398 मेट्रिक टन, सुपर फॉस्फेट 8898 मेट्रिक टन, अमोनियम सल्फेट 162 मेट्रिक टन, कुल 56943 मेट्रिक टन की व्यवस्था की गई है। जिले में खरीफ मौसम वर्ष 2024 के लिये उर्वरकों की कोई कमी नही है, जिले में नियमित उर्वरक प्राप्त हो रहा है । आगामी दिनों में 4-5 रेक इन्दौर एवं खण्डवा में प्रस्तावित है, जिससे भी यूरिया, डीएपी, कॉम्पलेक्स एवं एमओपी जिले को नियमित प्राप्त होगा ।

कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु एम.पी. किसान पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य

डिण्डोरी : कृषि उप संचालक ने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु शासन द्वारा संचालित एम.पी. किसान पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। अब कृषक बीज, कृषि उपकरण, सिंचाई उपकरण व अनेक लाभकारी योजनाओं का फायदा पंजीयन करवाकर ही प्राप्त कर सकेगें। एम.पी. किसान पोर्टल में पंजीयन नहीं कराने वाले कृषकों को कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजो में कृषक का आधार कार्ड (आधार-मोबाईल नंबर से लिंक हो), बही-खसरा (सभी खसरे आधार से लिंक होना चाहिए), कृषक की ई-मेल आई.डी., कृषक का जाति प्रमाण पत्र यदि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो) अतः कृषकों से अपील की गई है कि विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाईन पंजीयन कराएं, ताकि योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहें। किसी भी प्रकार की समस्या हेतु अनुविभागीय कृषि अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/बी.टी.एम./कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

पांरपरिक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर करें नैनो उर्वरकों का उपयोग

डिण्डोरी : कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितार्थ नैनो उर्वरक (नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी) अत्याधिक कुशल उर्वरक है जो सूक्ष्म कणों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदाय करते हैं। पारंपरिक रासायनिक उर्वरक डीएपी एवं यूरिया के स्थान पर तरल नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उपयोग का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। जिसमें पारंपरिक रासायनिक उर्वरक (यूरिया एवं डीएपी) की दक्षता 25 प्रतिशत है तथा नैनो उर्वरक की दक्षता 85 से 90 प्रतिशत है। इसी प्रकार से पारंपरिक रासायनिक उर्वरक (यूरिया एवं डीएपी) की एक बोरी के समतुल्य में नैनो उर्वरक 500 मिली. (1 बोतल) है। जिसके अनुसार पारंपरिक रासायनिक उर्वरक (यूरिया एवं डीएपी) की दर यूरिया 266.5 रूपये प्रति 45 किलोग्राम डीएपी 1350 रूपये प्रति 50 किलोग्राम के मुकाबले नैनो यूरिया की दर 240 रूपये प्रति 500 मिली एवं नैनो डीएपी की दर 600 रूपये प्रति 500 मिली है। तुलनात्मक व्यय में पारंपरिक रासायनिक उर्वरक में यूरिया का व्यय 533 रूपये प्रति 90 किलोग्राम प्रति एकड़, डीएपी का व्यय 1350 रूपये प्रति 50 किलोग्राम एकड़ है। जबकि नैनो उर्वरक में नैनो यूरिया का व्यय 240 रूपये प्रति 500 मिली प्रति एकड़ तथा नैनो डीएपी का व्यय 600 रूपये प्रति 500 मिली प्रति एकड़ है।

विभाग द्वारा बताया गया कि किसान नैनो उर्वरक का 2-4 मि.ली./लीटर पानी का घोल का खड़ी फसल में छिड़काव करें, इसका उपयोग सभी प्रकार के फसलो पर किया जा सकता है। पहला छिड़काव फसल के अंकूरण के 30 दिन बाद एवं दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20-25 दिन बाद करें। नैनो उर्वरक फसल की उपज की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है एवं फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी करके किसानों की आय में वृद्धि करता है। एवं पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। अतः कृषकों से अपील की जा रही है कि पारंपरिक रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं डी.ए.पी. के स्थान पर नैनो उर्वरकों का ही उपयोग करें।

कृषि के क्षेत्र में बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिये मौसम एप की शुरुआत एक नई क्रांति

छिन्दवाडा : उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मौसम एप Mausam App IMD किसानों को सटीक और समय पर मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। इस मौसम एप का मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाना और उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एप स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवाओं की गति की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा यह एप किसानों की फसल के प्रकार, बोआई के समय और कीट नियंत्रण के उपायों के बारे में भी मार्गदर्शन करेगा।

उन्होंने बताया कि मौसम एप मौसम के विस्तृत पूर्वानुमान को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर प्रदान करता है। जिससे किसान फसल के महत्वपूर्ण चरणों में सही निर्णय ले सके। विभिन्न फसलों के लिए मौसम के अनुसार उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं, जिससे उत्पादन में सुधार होता है और नुकसान कम होता है। एप संभावित मौसम जोखिमों जैसे तूफान, भारी बारिश या सूखे के बारे में अलर्ट भेजता है, जिससे किसान समय पर तैयार हो सकें। सहायक संसाधन के रूप में किसानों के लिए वीडियोज, लेख और विशेषज्ञों की सलाह भी उपलब्ध है, जिससे वे नवीनतम कृषि तकनीकों और उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यह एप किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इससे किसानों की उत्पादकता में वृध्दि होगी और उनके मुनाफे में भी सुधार होगा।

विभिन्न कृषि आदान विक्रेताओ के प्रतिष्ठानो का हुआ औचक निरीक्षण

जबलपुर : किसानो को उच्च गुणवत्ता का बीज एव खाद उचित स्तर पर प्राप्त हो सके, इसके लिये कृषि विभाग सजग है तथा अधिकारियों के द्वारा निरन्तर कृषि आदान सामग्री विक्रेताओ के प्रतिष्ठानो का औचक निरीक्षण किया जा रहा है तथा जहाँ भी कमियाँ मिलती है उनको नोटिस जारी कर उन पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी श्रृखंला में आज पाटन विकासखंड के विभिन्न कृषि आदान विक्रेताओ के प्रतिष्ठानो का औचक निरीक्षण सहायक संचालक कृषि कीर्ति वर्मा एवं जिला परामर्शदाता मुकेश मीणा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री गणेश फर्टीलाइजर एवं राहुल कृषि केन्द्र का गोदाम में भंडारित खाद का पी.ओ.एस. मशीन से मिलान किया गया। गणेश फर्टीलाइजर द्वारा पी.सी. जुडवाये बगैर बीज का भंडारण किया गया था। अतः उनको नोटिस जारी कर ऐसा न करने की हिदायत दी गई। जिला स्तरीय गठित दल के दौरे की जानकारी लगते ही कई विक्रेताओ द्वारा जाँच से बचने के लिये अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिये गये। ऐसे प्रतिष्ठान पचौरी कृषि केन्द्र पाटन, माँ रेवा कृपा कृषि केन्द्र पाटन, शिवशक्ति कृषि केन्द्र पाटन, किसान एग्रो सीड्स पाटन, माँ अमृता एग्रो एंड सेल्स पाटन, श्री पारस बीज भंडार पाटन, प्रशान्त बीज भंडार पाटन एवं अरविन्द बीज भंडार पाटन प्रतिष्ठानो में नोटिस चस्पा किये गये तथा उनको तीन दिवस के अंदर अपने समस्त रिकार्ड के साथ उप संचालक कृषि कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई, ऐसा न करने पर उनके लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।

इसके बाद दल के द्वारा प्रगति सीड्स के ग्रेडर यूनिट का निरीक्षण किया गया तथा समिति द्वारा उत्पादित बीज का संपूर्ण रिकार्ड देखा गया तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीकान्त यादव द्वारा बीज के सेंपल लिये गये और गुणवत्ता परीक्षण के लिये प्रयोगशाला भेजे गये। बीज उत्पादन समिति द्वारा किसानो के यहाँ लिये गये बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं उनके द्वारा उत्पादित बीज की मात्रा एवं ग्रेडिंग के बाद पैकिंग के लिये तैयार बीज की मात्रा के स्टाक का मिलान किया गया तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल किये गये लॉट की जानकारी मौके पर तुरंत उपलब्ध नही कराने के कारण उक्त जानकारी उप संचालक कृषि कार्यालय में दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

फसलों के लिये डी ए पी से ज्यादा उपयोगी है एन पी के

जबलपुर : किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के किसानों को खरीफ फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उप संचालक कृषि रवि आम्रवंशी के मुताबिक फसलों के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश पोषक तत्व आवश्यक होते हैं । डी ए पी की तुलना में एन पी के सस्ता और अच्छा उर्वरक होता है । इसमें पोटाश की मात्रा का भी समावेश होता है। एनपीके ग्रेड के उर्वरक समितियों एवं पंजीकृत कृषि केन्द्रों में उपलब्ध है। उन्होंने किसानों को फसलों में अंधाधुंध उर्वरकों के उपयोग से बचते हुए समन्वित प्रबंधन में गोबर की खाद, केंचुआ की खाद एवं हरी खाद के साथ ही अनुशंसित मात्रा में एन पी के का फसलों के अनुरूप उपयोग करने की सलाह दी है। श्री आम्रवंशी ने बताया कि धान एवं मक्का जिले में खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों के लिए किसानों को सामान्यतः 80 से100 किलोग्राम एन पी के प्रति एकड़ बोनी के समय आधार उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवश्यकता से अधिक उर्वरक का प्रयोग किसी भी हालत में ठीक नहीं है। यह फसल की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी, पानी की दशा भी खराब करते है तथा फसलों में कीड़े और बीमारियों को बढ़ावा देते है। जिसके नियंत्रण के लिए किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उप संचासक कृषि ने बताया कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और भूमि, जल एवं पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एन पी के के प्रयोग से फसलों में पोटाश की मात्रा बिना अतिरिक्त पैसे खर्च किये प्राप्त होती है। जिससे उत्पादन की गुणवत्ता जैसे- बीजों में चमक, बीजों के वजन में वृद्धि होती है। जिससे आपके उत्पाद का बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

हायर डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट
20 सप्ताह पाठ्यक्रम सत्र का समापन

भोपाल । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सघं मर्यादित, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2023-24 हेतु सहकारी प्रबंध पर उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) के कोर्स दिनांक 01.01.2024 से 30.05.2024 तक चतुर्थ सत्र का ऑनलाईन संचालन सत्र समन्वक श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता एवं तकनीकी सहायक श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव प्रशिक्षक द्वारा किया गया। कोर्स के माध्यम से सहकारिता की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई। सहकारी प्रबंध पर उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में निम्नांकित व्याख्याताओं / अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अपने ज्ञान से उद्भूत किया गया। जिसमें सहकारिता विषय पर श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल एवं श्री ए.के. जोशी सेवानिवृत प्राचार्य सह. प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, सहकारी प्रबंध एवं बैंकिंग विषय पर श्री अभय गोखले, सेवानिवृत प्रबंधक, अपेक्स बैंक एवं श्री दिलीप मरमट प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर, वित्तीय लेखांकन एवं अंकेक्षण विषय पर डॉ. आनंद पराडकर, लेखाकंन व्याख्याता भोपाल एवं श्री अभय गोखले, से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक, भोपाल, सहकारी कार्यप्रणाली वैधानिक प्रशासन विषय पर श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल, व्यवसाय विकास नियोजन, वित्तीय प्रबंध विषय पर श्री व्ही.के.बर्वे, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं श्री ए. के. जोशी से.नि. प्रा. भोपाल एवं कम्प्यूटर प्रबंध एवं सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता, मुख्यालय एवं श्री शिरीष पुरोहित, प्रभारी प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव द्वारा पाठ्यक्रम सम्पन्न कराया गया।

संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि ऑनलाईन पाठ्यक्रम सत्र क्रमाक 04 (दिनांक 11 जनवरी 2024 से 2024 से 30.05.2024 तक) की मुख्य परीक्षा दिनांक 21.05.2024 से 30.05.2024 तक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में आयोजित की गई । एचडीसीएम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य, संघ कि और से ढेर सारी शुभकामनाएं।

कृषि वैज्ञानिकों ने धान की खेती में श्री तकनीक की दी जानकारी

सिवनी : कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी की दर्पण सभागार में धान की उत्तम खेती हेतु एस आर आई (श्री) तकनीकी का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया श्री पद्धति से धान की खेती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में डी. एस. ग्रुप के अंतर्गत ग्राम कुरई, बरघाट एवं सिवनी के लगभग 40 से अधिक कृषकों ने भाग लिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल धान में एस आर आई पद्धति से खेती करने के विषय में केंद्र के प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने बताया कि धान की खेती में परंपरागत खेती से उत्पादन श्री पद्धति से उत्पादन अधिक प्राप्त होता है श्री पद्धति जिसे सिस्टम आफ राईस इंटेंशिफिकेशन (एस. आर. आई) या धान की मेडागास्कर पद्धति के नाम से जाना जाता है जिसे फ्रांस के धर्मगुरु फादर हेनरी दी लौलाने ने 1980 के दशक के

दौरान मेडागास्कर में धान की श्री पद्धति का विकास किया था, वर्तमान में धान की श्री पद्धति पानी की बचत के साथ ही प्रति हेक्टेयर कम बीज उपयोग एवं अधिक उत्पादन की दृष्टिकोण से उत्तम तकनीक है धान की श्री पद्धति से खेती हेतु तकनीकी मार्गदर्शन बीज का चुनाव, खेत की तैयारी एवं महत्वपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन वैज्ञानिक डॉ. निखिल सिंह द्वारा प्रदान किया गया इसके अलावा वर्तमान में धान की खेती में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में विस्तार से जानकारी डॉ. के. के. देशमुख मृदा वैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई धान की मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन तकनीक पर किसानों के साथ वैज्ञानिकों की परिचर्चा भी आयोजित की गई, कार्यक्रम के समापन अवसर उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ के कर कमलों द्वारा समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य पत्रक वितरित किया गया, कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह ठाकुर वैज्ञानिक द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन डी. एस. ग्रुप के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री संदीप शर्मा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र की समस्त वैज्ञानिक डॉ. शेखर सिंह बघेल, डॉ. के. के. देशमुख, डॉ. निखिल सिंह, डॉ. राजेन्द्र सिहं ठाकुर, डॉ. जी. के. राणा, इंजी. कुमार सोनी, श्रीमति करूणा मेश्राम पगारे ने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।